भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
अतारांकित प्रश्न सं.430
दिनांक 19 नवम्बर, 2019 को उत्तर देने के लिए

एफपीआई की स्थापना

430. डॉ. सुभाष सरकार:
श्री जी.एम.सिद्देश्वर:
श्रीमती लॉकेट चटर्जी:
श्री रामदास तडस:
श्री सी.पी.जोशी:
क्या **खाद्यप्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पश्चिम बंगाल के बांकुरा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तर पूर्वी क्षेत्र सहित देश में कार्यरत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (एफपीआई) का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या यह सच है कि इन उद्योगों में रोजगार पैदा करने की दृष्टि से विभिन्न राज्यों से एफपीआई स्थापित करने के प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास विचाराधीन हैं;
(ग) यदि हां, तो इन प्रस्तावों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;
(ड.) क्या सरकार का उत्तर प्रदेश, राजस्थान सहित देश के विभिन्न राज्यों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की कोई नई इकाई स्थापित करने का विचार है; और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क): उद्योगों के नवीनतम वार्षिक सर्वेक्षण, 2016-17 के अनुसार पंजीकृत प्रचालनरत खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों/फैक्टरियों की राज्य-वार संख्या **संलग्नक-I** में दी गई है ।

(ख) से (घ): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय केंद्रीय क्षेत्र की एक स्कीम – प्रधान मंत्री किसान सम्पदा योजना (पीएमकेएसवाई) कार्यान्वित कर रहा है जिसमें चार पुरानी स्कीमें (i) मेगा फूड पार्क; (ii) एकीकृत शीत श्रृंखला एवं मूल्यवर्धन अवसंरचना (कोल्ड चेन); (iii)खाद्य संरक्षा एवं गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना (एफएसडब्लूएआई); (iv) मानव संसाधन एवं संस्थान (एचआरआई)एवं तीन नई स्कीमें (i) खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमता सृजन/विस्तार (यूनिट स्कीम); (ii)कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर अवसंरचना (एपीसी); (iii) बैकवर्ड तथा फारवर्ड लिंकेज सृजन (बीएफएल) हैं । मंत्रालय प्रायोगिक आधार पर चयनित राज्यों में टमाटर, प्याज और आलू (टीओपी) फसलों की मूल्य/आपूर्ति श्रृंखला के एकीकृत विकास हेतु नवम्बर, 2018 से पीएमकेएसवाई की वर्टीकल स्कीम के रूप में केंद्रीय क्षेत्र एक अन्य स्कीम "ऑपरेशन ग्रीन्स"भी कार्यान्वित कर रहा है , चयनित राज्यों में कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं । विभिन्न राज्यों से इन स्कीमों के अंतर्गत प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं और पिछले 3 वर्षों के दौरान कुल 275 परियोजनाएं अनुमोदित की गईं हैं । पिछले 3 वर्षों के दौरान राज्य-वार और स्कीम-वार अनुमोदित की गईं परियोजनाएं **संलग्नक-II** में दर्शाई गईं हैं ।

(ड.) और (च): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय किसी भी राज्य में अपने स्तर पर कोई भी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग/परियोजनाएं/यूनिटें स्थापित नहीं करता है । यह खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों/यूनिटों/परियोजनाओं की स्थापना करने के लिए पीएमकेएसवाई की विभिन्न घटक स्कीमों के अंतर्गत व्यक्तियों, किसानों, उद्यमियों, संगठनों जैसे केंद्र और राज्य सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/संयुक्त उद्यमों/किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओज)/एनजीओज/सहकारिताओं/एसएचजीज/सार्वजनिक एवं निजी कंपनियों इत्यादि को अनुदान सहायता के रूप में पूंजी सब्सिडी के तौर पर वित्तीय सहायता देता है । पात्र आवेदक को वित्तीय सहायता मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी की गई अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के प्रत्युत्तर में दी जाती है ।

*****

संलग्नक-I

एफपीआई की स्थापना के बारे में दिनांक 19.11.2019 को लोक सभा में पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न सं.430 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण ।

वर्ष 2016-17 में पंजीकृत प्रचालनरत खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों/फैक्टरियों की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कार्यशील खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों/फैक्टरियों की संख्या
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	4
2	आंध्र प्रदेश	4702
3	अरुणाचल प्रदेश	29
4	असम	1389
5	बिहार	751
6	चंडीगढ़	14
7	छत्तीसगढ़	1168
8	दादरा और नगर हवेली	7
9	दमन और दीव	31
10	दिल्ली	140
11	गोवा	97
12	गुजरात	1745
13	हरियाणा	751
14	हिमाचल प्रदेश	169
15	जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख	164
16	झारखंड	220
17	कर्नाटक	2037
18	केरल	1556
19	मध्य प्रदेश	818
20	महाराष्ट्र	2424
21	मणिपुर	26
22	मेघालय	25
23	नागालैंड	21
24	ओडिशा	1007
25	पुदुच्चेरी	55
26	पंजाब	2498
27	राजस्थान	821
28	सिक्किम	19
29	तमिलनाडु	4583
30	तेलंगाना	3443
31	त्रिपुरा	91
32	उत्तर प्रदेश	1752
33	उत्तराखंड	305
34	पश्चिम बंगाल	1849
कुल		**34,711**

स्रोत: उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण

संलग्नक-II

एफपीआई की स्थापना के बारे में दिनांक 19.11.2019 को लोक सभा में पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्नसं.430 के भाग (ख) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण ।

पिछले 3 वर्षों के दौरान पीएमकेएसवाई के अंतर्गत अनुमोदित की गईं खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं की राज्य-वार संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एमएफपी	कोल्ड चेन	सीईएफपीपीसी (यूनिट)	कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर	बैकवर्ड एवं फारवर्ड लिंकेज	ऑपरेशन ग्रीन्स
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	1	0	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	0	17	0	1	1	1
3	अरुणाचल प्रदेश	1	1	0	0	0	0
4	असम	0	0	2	0	0	0
5	बिहार	0	1	0	1	0	0
6	छत्तीसगढ़	0	0	2	0	1	0
7	गोवा	0	0	1	0	0	0
8	गुजरात	1	11	15	3	7	1
9	हरियाणा	1	5	14	5	1	0
10	हिमाचल प्रदेश	0	10	11	1	2	0
11	जम्मू और कश्मीर	0	2	13	1	2	0
12	**कर्नाटक**	**1**	**9**	**11**	**5**	**2**	**0**
13	केरल	0	6	4	1	2	0
14	मध्य प्रदेश	0	2	8	5	1	0
15	महाराष्ट्र	0	40	28	6	12	0
16	मणिपुर	0	0	1	1	1	0
17	मेघालय	0	0	1	0	0	0
18	मिजोरम	0	0	1	0	0	0
19	नागालैंड	1	2	4	0	0	0
20	ओडिशा	0	1	2	0	2	0
21	पुदुच्चेरी	0	0	0	1	0	0
22	पंजाब	0	8	4	3	4	0
23	राजस्थान	**0**	**6**	**8**	**1**	**6**	**0**
24	सिक्किम	0	0	1	0	0	0
25	तमिलनाडु	0	8	18	0	9	0
26	तेलंगाना	0	6	1	1	1	0
27	**उत्तर प्रदेश**	**2**	**17**	**18**	**2**	**4**	**0**
28	उत्तराखंड	0	10	6	1	2	0
29	**पश्चिम बंगाल**	**0**	**3**	**6**	**0**	**1**	**0**
	कुल	**7**	**166**	**180**	**39**	**61**	**2**